चुनावी बॉण्ड योजना

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी की है कि चुनावी बॉण्ड योजना "चयनात्मक अनामता (Selective Anonymity) " से ग्रस्त है।
- कुछ लोगों की सूचनाएं बाहर आ सकती हैं, जबकि कुछ के मामले में नहीं आ सकती हैं।
- इसके कारण यह योजना "पूर्णत: इन्फॉर्मेशन ब्लैकहोल" बन गई है, अर्थात सूचनाएं बाहर ही नहीं आ पाती हैं।
- चंदा देने वाला, चुनावी बॉण्ड खरीदने के लिए बड़ी राशि निवेश करने की बजाय, अलग-अलग खरीदारों से छोटी राशि के बॉण्ड एकत्र कर सकता है।
- सत्तरुढ़ दल के लिए विपक्षी दलों को मिले चुनावी चंदे की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना को 2017 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। यह एक ब्याज- मुक्त धारक साधन (Bearer Instruments) है।
- भारतीय स्टेट बैंक इनकी बिक्री के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक है।

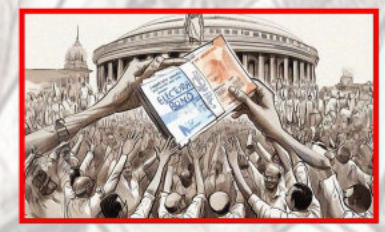

'राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक (NLMs)' >>>>

'राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक (NLMs)'

- NLMs सरकार द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी जैसे "स्वतंत्र पर्यवेक्षक" होंगे।
- सरकार व्यक्तियों के साथ-साथ संस्थानों को भी NLMs नियुक्त कर सकती है।
- खुलना: मौगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना -
- NLMs की आवश्यकता क्यों: सरकार NLMs की नियुक्ति इसलिए करती है, ताकि योजनाओं को लागू करते समय कार्यान्वयन एजेंसियों के समक्ष आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सके।
- NLMs यह निर्धारित करेंगे कि क्या योजना के तहत तकनीशियनों किसानों को प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं और क्या उत्पन्न डेटा अपलोड किया गया है।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLMs): इस मिशन में कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्रक में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, इसमें पशु आहार व चारे की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): इस मिशन को देशज गोवंशीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): इस मिशन को देशज गोवंशीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम: इसे दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा संगठित दुग्ध वितरकों से दूध की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH&DCP): रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, पशु चिकित्सकों के क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना।

महादेई वन्यजीव अभयारण्य (MWS) >>>>

महादेई वन्यजीव अभयारण्य

- हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य (MWS) में एक टाइगर रिज़र्व अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।
- गोवा सरकार ने न्यायालय के इस निर्देश का पालन नहीं किया है।
- इस कारण गोवा सरकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना संबंधी याचिका दायर की गई है।
- MWS को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
- यह महादेई नदी बेसिन का हिस्सा है।
- महादेई नदी का जलग्रहण क्षेत्र गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है।
- पाई जाने वाली वनस्पतियों में आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध- सदाबहार वन और झाड़ियां शामिल हैं।
- यहां पवित्र उपवन निरंकारची अवस्थित है।
- इस उपवन में पादप की एक विशिष्ट प्रजाति मिरिस्टिका मालाबारिका की अधिकता है। यह इस स्थल की एक संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है।
- जीव-जंतु: रूबी-थ्रोटेड येलो बुलबुल (गोवा का राजकीय पक्षी), एटलस मॉथ, बाघ आदि

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक >>>>

राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक

- हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने चार वर्षों के उपरांत राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित किया।
- सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी एक वार्षिक मूल्यांकन है।
- इसे देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 2018-19 में शुरू किया गया था।
- मूल्यांकन के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश।
- 2023 सूचकांक में शामिल एक नए पैरामीटर के समायोजन के बाद, 20 में से 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में कम 2023 स्कोर दर्ज किया।
- पांच वर्षों में स्कोर में सबसे भारी गिरावट महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में देखी गई।
- सबसे खराब गिरावट फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर में दर्ज की गई है। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों ने इस पैरामीटर के लिए कम स्कोर दर्ज किया।
- इस बीच, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड ने अनुपालन' पैरामीटर के लिए कम स्कोर दर्ज किया। 2023 सूचकांक में, 'एसएफएसआई रैंक में सुधार' नामक एक नया पैरामीटर जोड़ा गया।